



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 19, 2013/भाद्र 28, 1935

No. 206]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 19, 2013/BHADRA 28, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 सितंबर, 2013

मध्यावधि समीक्षा

विषय : चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित ग्लास फाइबर और उसकी वस्तुओं के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की शुरुआत ।

सं. 14/21/2013—डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे " पाटनरोधी नियमावली" कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे "प्राधिकारी") कहा गया है, ने 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं० 14/28/2009—डी जी ए डी के तहत चीन जन.गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित ग्लास रोविंग [असेम्बल्ड रोविंग (ए आर), डायरेक्ट रोविंग (डी आर)], ग्लास चोपड़ स्ट्रैंड्स (सी एस), ग्लास चोपड़ स्ट्रैंड मैट्स (सी एस एम) सहित ग्लास फाइबर (जिन्हें आगे "संबद्ध वस्तु" कहा गया है) के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अपने अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे । विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर रखी गईं मदें हैं—ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, वूल रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन, ग्लास यार्न, ग्लास वोवन फैब्रिक, थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए नियम ग्लास वोवन [रोविंग और चौकड़ स्ट्रैंड्स, बैटरी सेपरेटर में प्रयुक्त माइक्रो ग्लास फाइबर, सर्फेस मैट/सर्फेस व्हील/टिश्यू ।

2. और यतः संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क सीमाशुल्क अधिनियम सं० 30/2011, 4 मार्च, 2011 की सी.शु. अधिसूचना और 31 मार्च, 2011 के शुद्धि-पत्र के तहत लगाया गया था ।

3. और यतः अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध रहित माइक्रो ग्लास फाइबर को उपर्युक्त पाटनरोधी अधिसूचना तथा सीमाशुल्क अधिसूचना के दायरे से बाहर रखने हेतु निर्दिष्ट प्राधिकारी को मै0 रमन फाइबर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर से एक आवेदन प्राप्त हुआ है। प्राधिकारी ने आवेदन की जांच की है और उनका विचार यह है कि उपर्युक्त अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क के दायरे से माइक्रो ग्लास फाइबर को अलग रखने की जरूरत के बारे में कोई निष्कर्ष मध्यावधि समीक्षा के जरिए ही निकाला जा सकता है।

4. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में और वर्तमान समीक्षा आवेदन में भी विचाराधीन उत्पाद ग्लास रोविंग [असेम्बल्ड रोविंग (ए आर), डायरेक्ट रोविंग (डी आर)], ग्लास चोपड़ स्ट्रैंड्स (सी एस), ग्लास चोपड़ स्ट्रैंड मैट्स (सी एस एम) सहित ग्लास फाइबर है। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशिष्ट रूप से बाहर रखी गई मदे हैं—ग्लास वूल, फाइबर ग्लास वूल, वूल रूप में फाइबर ग्लास इंसुलेशन, ग्लास यार्न, ग्लास वोवन फैब्रिक, ग्लास फाइबर फैब्रिक थर्मोप्लास्टिक अनुप्रयोगों के लिए नियम ग्लास वोवन रोविंग और चोपड़ स्ट्रैंड्स, बैटरी सेपरेटर में प्रयुक्त माइक्रो ग्लास फाइबर, सर्फेस मैट/सर्फेस वेल/टिशू। ग्लास फाइबर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 70 और सुमेलित वस्तु वर्णन एवं कोडिंग प्रणाली पर आधारित आई टी सी वर्गीकरण में उप शीर्ष 7019 के अंतर्गत वर्गीकृत है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि यह मध्यावधि समीक्षा जांच इस बात की जांच तक सीमित है कि क्या अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध रहित माइक्रो ग्लास फाइबर को 6 जनवरी, 2011 की डी जी ए डी अधिसूचना सं0 14/28/2009—डी जी ए डी और 4 मार्च, 2011 की सी.शु. अधिसूचना सं0 30/2011 तथा 31 मार्च, 2011 के शुद्धि-पत्र के जरिए संस्तुत पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

5. जांच की शुरुआत

अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली में अन्य बातों के साथ-साथ प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा करने की अपेक्षा की गई है। मै. रमन फाइबर साइंस प्रा. लि., बंगलौर ने चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा शुरू करने की जरूरत की पुष्टि करते हुए एक आवेदन दायर किया है और अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध रहित माइक्रो ग्लास फाइबर को पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के क्षेत्र और दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया है। विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1 क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 क(5) के उपबंधों के अंतर्गत इस चरण पर पूर्व में संस्तुत पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि की समीक्षा करना उचित होगा। तथापि, मध्यावधि समीक्षा इस जांच तक सीमित है कि क्या अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध रहित माइक्रो ग्लास फाइबर को संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु पर पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखना अपेक्षित है।

शामिल देश

6. वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन.गण. है।

समीक्षा के आधार

7. आवेदक ने दावा किया है कि भारत के भीतर ऐसा कोई विनिर्माता नहीं है जो माइक्रो ग्लास फाइबर (एम जी एफ) का विनिर्माण और उसकी आपूर्ति करता हो। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह बताया है कि माइक्रो ग्लास फाइबर की तकनीकी विशेषताएं और विनिर्माण प्रक्रिया ग्लास फाइबर से भिन्न हैं। याचिकाकर्ता ने यह तर्क दिया है कि एम जी एफ के उपयोग हेतु की गई फ्लेम अटेनिवेशन प्रोसेस के लिए मुख्य निविष्टि के रूप में प्राकृतिक गैस के प्रयोग की जरूरत होती है और इसका हिस्सा एम जी एफ की लागत के 80 प्रतिशत से अधिक होता है। इसी वजह से एम जी एफ को केवल उन स्थानों पर तैयार किया जाता है जहां प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है अन्यथा यह अलाभकारी बन जाएगा। इसके अलावा, फ्लेम अटेन्यूएशन प्रौद्योगिकी के लिए विशेष नियंत्रणों की जरूरत होती है और इसकी अपनी प्रक्रियागत तकनीकें होती हैं। इन्हीं कारणों से याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि पश्चिमी गोलार्ध में एम जी एफ का निर्माण केवल दो कंपनियों (i) अमरीका में जोन्स मनाविले कॉर्प और (ii) जर्मनी में लौशा फाइबर द्वारा किया जाता है। उपर्युक्त कंपनियों के अलावा चीन में कुछ कंपनियों द्वारा एम जी एफ का विनिर्माण किया जाता है। चीन में ही एम जी एफ का एक बड़ा बाजार है और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्तियों के कारण वह इस सामग्री के व्यवहार्य प्रतिस्पर्धी और आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि इसके विपरीत भारत सहित एशिया में कहीं भी एम जी एफ का कोई विनिर्माता नहीं है। अतः उन्होंने यह बताया है कि भारत में प्रयोग किए जा रहे समस्त एम जी एफ का आयात उपर्युक्त में से एक या दूसरे स्रोत से किया जा रहा है और एम जी एफ के आयातों के कारण स्पष्ट रूप से कोई घरेलू क्षति नहीं हुई है। आगे यह बताया गया है कि एम जी एफ की वैश्विक कीमतें पारंपरिक ग्लास फाइबर की कीमत से काफी अधिक हैं—जो पारंपरिक ग्लास फाइबर की 1-2 अम.डा. प्रति किग्रा. की तुलना में 3-10 अम.

डा. प्रति किग्रा. के बीच हैं । भौतिक रूप से भी एम जी एफ में नितांत अलग दिखावट एवं सर्फेस क्षेत्र होता है अर्थात् पारंपरिक ग्लास फाइबर के एक्सट्रूडेड स्ट्रैंड्स के विपरीत काटन वूल के समान अधिक होता है । यह अत्यंत उच्च बल्क घनत्व और परिष्कृत फाइबर व्यास का होता है और उसकी अन्य विशेषताएं उसे पारंपरिक रिइन्फोर्समेंट अनुप्रयोगों के लिए उपयोगहीन बना देती हैं जिनमें नियमित ग्लास फाइबर का उपयोग होता है और इसीलिए एम जी एफ तथा पारंपरिक ग्लास फाइबर वाणिज्यिक एवं भौतिक रूप से अप्रतिस्थापनीय हैं । पूर्वोक्त पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि किसी अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंधरहित एम जी एफ को 6 जनवरी, 2011 की पाटनरोधी जांच संस्तुतिकारी अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।

प्रक्रिया

8. 6 जनवरी, 2011 की पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 14/28/2009—डी जी ए डी के तहत अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम और 4 मार्च, 2011 की सी.शु. अधिसूचना सं० 30/2011 एवं 31 मार्च, 2011 के शुद्धिपत्र के तहत लगाए गए परिणामी पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने का निर्णय लेने के बाद प्राधिकारी यह जांच करने के लिए एतद्वारा मध्यावधि समीक्षा जांच शुरू करते हैं कि क्या अंतिम प्रयोग संबंधी प्रतिबंध रहित माइक्रोग्लास फाइबर को अधिनियम, 1995 और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के दायरे से बाहर रखे जाने की जरूरत है ।

सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में उसके दूतावास/प्रतिनिधियों के जरिए उसकी सरकार, से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने और निम्नलिखित पते पर प्राधिकारी को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,

वाणिज्य विभाग,

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डी जी ए डी),

कमरा सं. 240, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

10. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अनुरोध कर सकता है ।

समय सीमा

11. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिन (40 दिन) से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में पहुंच जानी चाहिए । यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार, “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

12. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के बारे में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे (क) गोपनीय रूप में (शीर्षक, विषय सूची, पृष्ठ संख्या आदि) और (ख) अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) में प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रस्तुत की गई समस्त सूचना पर प्रत्येक पृष्ठ के सबसे ऊपर स्पष्ट रूप से “गोपनीय” या “अगोपनीय” अंकित होना चाहिए । किसी चित्रांकन के बिना प्रस्तुत सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे । गोपनीय रूपांतरण और अगोपनीय रूपांतरण प्रत्येक की दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

13. गोपनीय रूप में दावा की गई सूचना हेतु, सूचना प्रदाता के लिए यह अपेक्षित है कि वह प्रदान की गई सूचना के साथ इस आशय के यथोचित कारण का एक विवरण उपलब्ध कराए कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता और/अथवा ऐसी सूचना का सारांश क्यों संभव नहीं है ।

14. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई/सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है । अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके ।

तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है; तो प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

15. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अगर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

16. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी रिकॉर्ड में नहीं ले सकते हैं। संतुष्ट होने और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत को स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

17. नियम 6(7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

“उपलब्ध तथ्यों” का उपयोग

18. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास “उपलब्ध तथ्यों” के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. एस. दीपक, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 19th September, 2013

Mid-term review

Subject: Initiation of mid-term review of anti-dumping duty imposed on imports of glass fibre and articles thereof originating in or exported from China PR

No. 14/21/2013-DGAD: Whereas, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time, (herein after referred to as the ‘AD Rules’), vide Notification No.14/28/2009-DGAD dated 6th January, 2011 the Designated Authority (herein after referred to as ‘the Authority’) notified its final findings for imposition of Anti-Dumping Duty on import of glass fibre, including glass roving [assembled rovings (AR), direct rovings (DR)] glass chopped strands (CS), glass chopped strands mats (CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue (hereinafter referred to as ‘subject goods’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as ‘subject country’).

2. And WHEREAS antidumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No.30/2011 dated 4th March, 2011 and Corrigendum dated 31st March, 2011.

3. And WHEREAS an application has been received by the Authority from M/s Raman Fibre Science Private Limited, Bangalore for excluding micro-glass fibre without end-use restriction from the purview of the above referred Anti-dumping notification and Customs notification. The Authority has examined the application and is of the view that only through a mid-term review it can come to a conclusion the need to

exclude micro-glass fibre from the purview of anti-dumping duties notified by the above referred notifications.

4. **Product under consideration**

The product under consideration as in the original investigation and also in the present review application is glass fibre, including glass roving [assembled rovings(AR), direct rovings (DR)], glass chopped strands(CS), glass chopped strands mats(CSM). Specifically excluded from the scope of the product under consideration are glass wool, fibre glass wool, fibre glass insulation in wool form, glass yarn, glass woven fabrics, glass fibre fabric, glass woven rovings and chopped strands meant for thermoplastic applications, micro glass fibre used in battery separator, surface mat/surface veil/tissue. Glass fibre is classified under Chapter 70 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 7019 in the ITC classification based on harmonised commodity description and coding system.

As stated above, this mid-term review investigation is restricted to the examination of whether micro glass fibre without end-use restriction can be excluded from the purview of anti-dumping duties recommended through DGAD Notification No.14/28/2009-DGAD dated 6th January, 2011 and Customs Notification No.30/2011 dated 4th March, 2011 and corrigendum dated 31st March, 2011.

5. **Initiation**

The Act and the AD Rules, *inter-alia*, require the Authority to review from time to time the need for continuance of anti-dumping duty. M/s Raman Fibre Science Private Limited, Bangalore has filed an application substantiating the need for initiating a Mid- Term Review of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods originating in or exported from China PR and has requested to exclude micro-glass fibres without end-use restriction from the ambit and scope of the anti-dumping duty earlier imposed. Considering the duly substantiated request, the Authority considers that a mid-term review of the anti-dumping duty recommended earlier would be appropriate at this stage under the provisions of Section 9A (5) of the Act, read along with Rule 23(1A) of the Antidumping Rules. However, the scope of the mid-term review is restricted to examination of whether micro-glass fibres without end-use restriction are required to be excluded from the scope of the anti-dumping duty earlier imposed on the subject goods from the subject country.

Country Involved

6. The country involved in the present investigation is **China PR**.

Grounds for Review

7. The Applicant has claimed that there is no manufacturer within India who manufactures and can supply micro-glass fibres (MGF). Further the petitioner has stated that the technical characteristics of micro glass fibre and manufacturing process are different from that of glass fibre. The petitioner has contended that the flame attenuation process made to use MGF requires the use of natural gas as the main input and forms more than 80% of the cost of MGF. For this reason, MGF is made only in locations where natural gas is available plentiful as otherwise it would become uneconomical. Further, flame attenuation technology requires special controls and has its own process technicalities. For these reasons it is claimed by the petitioner that in the Western Hemisphere, MGF is made only by 2 companies (i) Johns Manville Corp in the United States and (ii) Lausha Fibre in Germany. Apart from the above companies, MGF is manufactured in China by some companies. China itself has a large market of MGF and with adequate supplies of natural gas has emerged as a viable competitor and supplier of this material. The petitioner states that by contrast, there are no manufacturers of MGF anywhere else in Asia – including India. Hence, they have stated that all MGF being used in India is being imported from one or the other of above sources and there is absolutely no domestic injury consequent to MGF imports. It has been further stated that MGF prices globally are far higher than conventional glass fibre – typically in the range of US\$ 3-10 per kg, as against US\$ 1-2 per kg for conventional glass fibre. Physically also MGF has a very distinct appearance and surface area – more like cotton wool as opposed to the extruded strands of conventional glass fibre. It's extremely high bulk density and fine fibre diameter and other characteristics render it unusable for conventional reinforcement applications in which regular glass fibre is used and therefore MGF and conventional glass fibre are commercially and physically non-substitutable. In view of the foregoing, the petitioner has requested that MGF without any end-use restrictions should be excluded from the purview of anti-dumping duty recommendation notification dated 6th January, 2011.

Procedure

8. Having decided to review the final findings notified vide Notification No. 14/28/2009-DGAD dated 6th January, 2011 earlier and consequent anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No: 30/2011 dated 4th March, 2011 and Corrigendum dated 31st March, 2011, the Authority hereby initiates a MTR investigation to examine whether micro-glass fibre without end-use restriction is required to be excluded from the scope of the anti-dumping duty earlier imposed in accordance with the Act, 1995 and the AD Rules.

Submission of Information

9. The exporters in the subject country, their government through their Embassy in India/representatives, the importers and users in India known to be concerned and the Domestic Industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the:

The Designated Authority
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, (DGAD),
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned hereinabove not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the “facts available” in accordance with the AD Rules.

Submission of information on confidential basis

12. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire’s response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

13. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

14. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

15. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

16. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

17. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Use of ‘facts available’

18. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the ‘facts available’ to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J. S. DEEPAK, Designated Authority